

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-45/2017

- *- मनोहरलाल पुत्र
- 2- रमेशकुमार पुत्र
- 3- प्रकाश पुत्र
- 4- रामभारण पुत्र
- 5- प्रभाती पत्नी

रैखा -

जाति बलाई निवपती रायपुर पाटन तहसील
नीमकाथाना जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

- 1- क्षेत्रीय वन अधिकारी रैंज पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।
- 2- राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक
9-6-2017 द्वारा सहायक
कलेक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना ।

---0---

उपस्थिति-

- 1-श्री बजरंगसिंह बोखावत एडवोकेट- अपीलान्ट
- 2-श्री विधाधर सूण्डा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगणा/अपीलान्ट्स ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधाना का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख०नं० 1153/15, 1153/18 कुल किता-2 रकबा 3.03 हैक्टर ग्राम रायपुर पाटन में स्थित है जिसके हाल खसरा नं० 1511/2053 रकबा 0.56 हैक्टर ख०नं० 1523 रकबा 0.04 हैक्टर, ख०नं० 1525 रकबा 0.97 हैक्टर, ख०नं० 1526 रकबा 0.45 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 2.02 हैक्टर दर्ज हो गया। पहले यह आराजी ख०नं० 1153 किस्म सिवायक दर्ज थी। उक्त आराजी में से प्रार्थीगणा के पिता/पति रेखा को भूमिदिन होने से 1.01 हैक्टर दिनांक 24-12-75 को आवंटन की गई थी। आवंटन के बाद इस आराजी का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर प्रार्थीगणा के पिता/पति के नाम दर्ज कर दी गई। रेखाराम को उक्त आराजी में ख०नं० 1153 में से 1.01 एवं 1.01 हैक्टर भूमि दो बाढ़ आवंटन की गई। तहसीलदार ने आवंटन के बाद मौका जांच कर मौके पर रेखा राम को 2.02 हैक्टर भूमि का कब्जा नाप जोख कर सम्भला दिया। किन्तु इस आराजी का नक्शे में तरमीम नहीं किया गया। तथा नये सैटलमेन्ट में गलत स्थ से तरमीम कर दी गई। जिसके कारण रेसपोडेन्ट सं०-1 इस आराजी पर जबरन पीलर रोप कर तारबन्दी कराने पर आमादा है। जबकि उक्त आराजी बाबत प्रार्थीगणा के पिता/पति रेखाराम ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर के यहां एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें इस आराजी बाबत दिनांक 15-9-71 को निर्णय पारित किया जिसमें इस आराजी को ~~ख०नं०~~ प्रार्थीगणा के पिता रेखा की ही मानी है। किन्तु अप्रार्थी संख्या-1 इस आराजी पर जबरन पीलर रोप कर तारबन्दी करने पर आमादा है। प्रार्थीगणा ने मना किया तो धमकी दी की यह आराजी उनकी है। इसमें तारबन्दी करेंगे जिस पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिस अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है। विवादित आराजी ख0न0 1153 में से अपीलान्ट के पिता/पति रेखा राम को 1.01 हैक्टर भूमि भूमिहिन मानकर आवंटित की थी। इसके बाद 1.01 हैक्टर भूमि ओर आवंटित की गई इस प्रकार रेखा को 2.02 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था, और तहसीलदार ने मौके पर नाप जोख कर कब्जा रेखा को सम्भलाया गया। तब से ही अपीलान्ट अपने पिता के जीवन काल से ही इस आराजी पर काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। रेखाराम के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गया। अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता रेखाराम ने इस आराजी को काफी मेहनत कर समतल एवं उपजाऊ बनाया है। जिस पर सैटलमेन्ट अधिकारी ने गलत तरमीम कर दी जिसके आधार पर रेस्पोजेन्ट इस आराजी पर जबरन पीलर रोप कर तारबन्दी करने पर आमादा है। जबकि अपीलान्ट इस आराजी पर अपने पिता के जीवनकाल से लगातार काबिज काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं। इस आराजी पर रेस्पोजेन्ट संख्या-1 जानबूझकर दक्षिणी पूर्वी हिस्से जिसमें अपीलान्ट का कुआ उक्त आराजी की सिचाई के लिये बना हुआ है उस पर जबरन वन विभाग की बताकर तारबन्दी करने पर आमादा है। अदालत मातहत ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर एवं अलाटमेन्ट आदेशों की अनदेखी कर आदेश पारित किया है अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सिवायक भूमि थी जिसमें से आराजी का दो बार अपीलान्ट के पिता/पति रेखाराम को भूमिहिन मानकर 1.01 एवं 1.01 हैक्टर कुल 2.02 हैक्टर भूमि का आवंटन आदेश आवंटन नियमों के तहत किया गया है। अतः तहसीलदार ने मौके पर नाप जोख कर

कब्जा सम्भलाया गया है। तब से अपीलान्ट इस आराजी पर लगातार काबिज है। इस आराजी पर रेस्पोंडेन्ट ने पहले भी बेदखल करने की काशीरा की थी तब हमारे पिता/पति रेखाराम ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर ने वन विभाग के बयान लेकर उक्त आराजी को वन विभाग की न मानकर अपीलान्ट्स की मानी थी। अदालत मातहत ने इस निर्णय का कोई अवलोकन न कर अपना निर्णय दिया है जो विधि के विपरित है। रेस्पोंडेन्ट अपीलान्ट को बेदखल कर देते हैं तो अपीलान्ट को अपूर्णित क्षति होगी। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।


विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने बहस में अपीलान्ट के कथनों को नकारते हुये अदालत मातहत के आदेश को उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि विज्ञापित दिनांक 9-4-1964 से आराजी खनं0 1153/1 रकबा 359 बीघा 19 बिस्वा को रक्षित वन भूमि घोषित की गई है। जिसका राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम बना हुआ है। अपीलान्ट केवल वन विभाग की आराजी पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। उक्त आराजी वन विभाग की है। जिसके लिए राजस्व न्यायालय को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। दौराने बहस नकल जमाबन्दी सं0-2071 से 2074 पेश की जिसमें विवादित आराजी वन विभाग की खातेदारी में दर्ज है। अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन कर अपना निर्णय दिया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकत नहीं है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है। बहस के समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट की अपील संख्या- 4099/2015 दिनांक 15-5-2015, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल दिनांक 23-2-15 पेश की जिसमें माननीय न्यायालय को वन विभाग की आराजी के बाबत सुनवाई का अधिकार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया । नकल
जमाबन्दी सं०-2071 से 2074 में ख०नं० 1511/2033, 1523, 1525, 1526 कुल
किता-4 रकबा 2.02 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्ट्स के नाम दर्ज है । जमाबन्दी
सं० 2056 से 2059 में आराजी ख०नं० 1153/15, 1153/18 कुल किता-2 रकबा
2.02 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्ट्स के पिता/पति के नाम दर्ज है । आवंटन
आदेश दिनांक 24-12-75 में ख०नं० 1153 में से 4 बीघा का आवंटन रेखाराम
पुत्र गोलाराम को किया गया है । नामा० सं० 406 में ख०नं० 1153 में से 4 बीघा
आवंटन आदेश के आधार पर रेखाराम पुत्र गोलाराम के नाम तस्दीक किया गया
है । जमाबन्दी सं०-2039 से 2042 में ख०नं० 1153/4 रकबा 4 बीघा नामा० सं०-82
624 से गैर खातेदारी से खातेदारी में रेखा पुत्र गोला हरिजन के नाम दर्ज है ।
आवंटन आदेश दिनांक 1-6-85 में ख०नं० 1153/1 में से 4 बीघा का आवंटन
रेखाराम को किया गया है । जमाबन्दी सं०-2071 से 2074 में विवादित भूमि
वन विभाग के नाम दर्ज है । राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-9।
का नोटिस दिनांक 14-4-68 के लिये जारी किया गया । सहायक वन बन्दोबस्त
अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांक 15-9-71 में वन विभाग ने स्वीकार किया
है कि उक्त आराजी वन सीमा के नजदीक है जिसको वन सीमा से पृथक करने में
कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर इस आराजी को अपीलान्ट के पिता रेखा की
ज्ञानकर आदेश पारित किया है । पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है
कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पिता/पति रेखाराम को नियमानुसार
आवंटित की है जिस पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा है जिसके लिये तहसीलदार
के राज० भू-राजस्व अधिनियम की धारा-9। के नोटिस जारी किये हुये है । तथा
सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर ने भी अपने निर्णय में इस आराजी को
वन विभाग की न मानकर वन सीमा से अलग करने के निर्देश देते हुये । इस
आराजी को अपीलान्ट के पिता रेखा के कब्जा का मत की मानी है । अपीलान्ट

का दावा विचाराधीन है। इस दौरान अपीलान्ट को विवादित आराजी से छेदखल किया जाता है तो अपीलान्ट को अमूर्ति क्षति होगी। राजस्व रेकार्ड के अनुसार एवं सहायक बन बन्दोस्त अधिकारी जयपुर के निर्णय से भी विवादित आराजी को अपीलान्ट के कब्जा कायम की मानी है जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में है। विद्वान वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों के तथ्य भिन्न होने से प्रकरणा पर चस्या नहीं है। प्रकरणा में पक्षकारों के मध्य ओर अधिक विवाद न हो इसके लिये हम विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित मानते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना का निर्णय दिनांक 9-6-2017 को खारिज किया जाता है तथा रेस्पोजेन्ट को पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.1.2018 को सुनाया गया।


१ भवराज लाल मेहरडा १
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर